मुख्यमंत्री ने गंग नहर में शताब्दी समारोह व्यापक स्तर पर मनाने के निर्देश दिए

शताब्दी कार्यक्रम सभी प्रमुख हेड रेगुलेटर्स तथा 12 अनाज मंडियों में आयोजित होंगे

जयपुर, 05 मई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा गंग नहर के निर्माण के 100 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर शताब्दी समारोह को लेकर महत्वपूर्ण बैठक ली। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि गंग नहर के शिवपुर हैड सहित सभी प्रमुख हैड रेगुलेटर्स पर नियमित रूप से कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। साथ ही, गंग नहर प्रणाली से जुडे क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर जनभागीदारी सुनिश्चित करते हुए पूरे वर्ष गतिविधियों का संचालन किया जाए।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को गंगनहर निर्माण के 100 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित होने वाले शताब्दी समारोह को लेकर अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक ली।

शताब्दी समारोह श्रृंखला के तहत नहर क्षेत्र की 12 अनाज मंडियों में किसानों के साथ संवाद कार्यक्रम भी शामिल है। इनमें किसानों को आधुनिक सिंचाई तकनीक, ड्रिप सिस्टम और जल संरक्षण जैसे विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही, नहरों की साफ-सफाई, उत्कृष्ट कार्य करने वाले जल उपयोगकर्ता संगठनों के अध्यक्षों का सम्मान एवं जन जागरुकता कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। इसके अलावा, साइकिल रैली, जल संरक्षण विषय पर नुक्कड़ नाटक सहित, विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से आमजन को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, ताकि गंग नहर शताब्दी समारोह जनभागीदारी और जागरुकता का व्यापक अभियान बन सके।

- महाराजा गंगासिंह द्वारा निर्मित गंग नहर में पहली बार पानी शिवपुर हेड से 26 अक्टूबर 1927 को आया था। राज्य सरकार अक्टूबर 2026 से 26 अक्टूबर 2027 तक इस उपलक्ष में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रही है।
- शताब्दी समारोह श्रृखंला के तहत नहर क्षेत्र में किसानों से संवाद कर उन्हें विशेषज्ञों के द्वारा आधुनिक सिंचाई तकनीक, ड्रिप सिस्टम, जल संरक्षण आदि की जानकारी दी जाएगी।

उल्लेखनीय है कि 5 दिसम्बर 1925 को महाराजा गंगासिंह द्वारा गंगनहर का निर्माण कार्य शुरू करवाया गया था तथा 26 अक्टूबर 1927 को गंगनहर की शिवपुर हैड में पहली बार पानी आया था। इसी उपलक्ष्य में 26 अक्टूबर 2026 से 26 अक्टूबर 2027 तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।

बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन विभाग अभय कुमार सहित, अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

अपराधिक अपील लंबित होने के कारण पेंशन परिलाभ नहीं रोक सकते

जयपुर, 5 मई। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि आपराधिक मामले में दोषमुक्त होने के बाद अपील लंबित होने के चलते रिटायर कर्मचारी के पेंशन परिलाभ नहीं रोके जा सकते हैं। इसके साथ ही, अदालत ने कहा है कि तीन माह में याचिकाकर्ता को समस्त बकाया परिलाभ छह फीसदी ब्याज सहित अदा किये जायें। जस्टिस रवि चिरानिया की एकलपीठ ने ये आदेश देवेन्द्र सलोल्या की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

- राजस्थान हाई कोर्ट ने अनुसूचित जाति, जनजाति वित्त व विकास निगम के कर्मचारी के मामले में आदेश दिया।

याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता अनुसूचित जाति, जनजाति वित्त व विकास निगम में कार्यरत था। उसके खिलाफ एसीबी में मामला लंबित होने के कारण उसे एसीपी का लाभ नहीं दिया गया। वहीं अप्रैल, 2016 में उसे एसीबी कोर्ट, कोटा ने दोषमुक्त कर दिया। इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपील दायर कर दी, जो लंबित चल रही है। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता 31 जनवरी, 2022 को रिटायर हो गया, लेकिन आपराधिक अपील के लंबित होने के कारण उसे पेंशन परिलाभ नहीं दिए गए, जिसे याचिकाकर्ता की ओर से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। याचिका पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को समस्त परिलाभ ब्याज सहित अदा करने को कहा है।

एसओजी पूरे प्रदेश में आरजीएचएस घोटाले की जाँच करेगा

स्वास्थ्य विभाग के मुकदमे से सामने आया कि कुछ सरकारी डॉक्टर निजी लैब संचालकों से मिलकर बड़े पैमाने पर सरकारी राशि का गबन कर रहे हैं

जयपुर, 5 मई। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (आरजीएचएस) में सामने आए बड़े घोटाले ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सीकर में एक डॉक्टर और एक लैब संचालक की गिरफ्तारी के बाद अब स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने जांच का दायरा बढ़ाते हुए पूरे प्रदेश में इसकी पड़ताल करने का निर्णय लिया है।

- कई मामलों में मरीजों के नाम पर जाँच की राशि उठाई गई, जबकि वे संबंधित डॉक्टर के पास गए ही नहीं थे। डॉक्टरों द्वारा परामर्श पर्ची पर अनावश्यक और महंगी जाँचे लिख कर बिल को कई गुना बढ़ा दिया जाता था।

एसओजी के डीआईजी परिस देशमुख ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से दर्ज मुकदमे में सामने आया है कि कुछ सरकारी डॉक्टरों और निजी लैब संचालकों ने मिलीभगत कर सरकारी राशि का बड़े पैमाने पर गबन किया। यह योजना सरकारी कर्मचारियों को कैशलेस उपचार उपलब्ध कराने के लिए है, जिसमें इलाज के खर्च का सरकार द्वारा अस्पतालों को पुनर्भरण किया जाता है।

प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि कई मामलों में मरीजों के नाम पर जांच की राशि उड़ाई गई, जबकि वे संबंधित डॉक्टर के पास गए ही नहीं थे। डॉक्टरों द्वारा परामर्श पर्चियों पर अनावश्यक और महंगी जांचें लिखी जाती थीं, जिन्हें एक ही निजी लैब में करवाकर बिल को कई गुना बढ़ा दिया जाता था।

तुलनात्मक विश्लेषण में कुछ लैब के बिल अन्य लैब्स की तुलना में कई गुना अधिक पाए गए, जिससे संदेह गहराया और मामला स्वास्थ्य विभाग के संज्ञान में आया।

अब तक की कार्रवाई में सीकर स्थित एक लैब के संचालक डॉ. बनवारी लाल को गिरफ्तार किया गया है, जबकि उसके दूसरे साझेदार का निधन हो चुका है। वहीं सरकारी डॉक्टर कमल कुमार अग्रवाल उर्फ केके अग्रवाल को भी गिरफ्तार किया गया है, जो फर्जी तरीके से जांच लिखने में शामिल था।

एसओजी के अनुसार, अब तक की जांच में एक ही एजेंसी द्वारा करोड़ों रुपए के गबन के प्रमाण सामने आए हैं। आगे जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

डीआईजी परिस देशमुख ने बताया कि फिलहाल दर्ज मुकदमा सीकर सहित दो जिलों से संबंधित है, लेकिन अब स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर पूरे राजस्थान में जांच का दायरा बढ़ाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की भूमिका पर उन्होंने कहा कि अभी तक किसी अधिकारी की संलिप्तता सामने नहीं आई है, लेकिन जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

एसओजी की इस कार्रवाई के बाद साफ है कि आरजीएचएस में लंबे समय से चल रहे इस संगठित फर्जीवाड़े पर अब कड़ा शिकंजा कसने की तैयारी है।

स्कूल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लिए आयोजित स्कूल व्याख्याता भर्ती-2024 की गत जून माह में हुई लिखित परीक्षा में याचिकाकर्ता शामिल हुआ था।

आयोग की ओर से मॉडल उत्तर कुंजी जारी कर प्रश्नों पर आपत्तियां मांगी, जिसमें याचिकाकर्ता ने आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि प्रश्न संख्या 71 का जवाब आयोग ने विकल्प संख्या 2 को सही माना है, जबकि मान्यता प्राप्त पुस्तकों में इस सवाल का जो जवाब बताया गया है, वह विकल्प संख्या 1 का है।

इसके बावजूद, आयोग की ओर से जारी अंतिम उत्तर कुंजी में विकल्प संख्या 2 के जवाब को ही सही माना गया, जिसे चुनौती देते हुए कहा गया कि इसी सवाल को आयोग ने साल 2022 की स्कूल व्याख्याता भर्ती में पूछा था और उस समय आयोग ने विकल्प संख्या 1 के जवाब को सही माना था।

दो साल में आयोग ने अपनी ओर से तय जवाब को ही बदल दिया।

याचिका में यह भी कहा गया कि माइनस मार्किंग की इस परीक्षा में याचिकाकर्ता केवल 0.66 अंक से कट ऑफ से बाहर हो गया है। ऐसे में यदि इस सवाल का विकल्प संख्या 1 में बताए जवाब को सही माना जाए तो उसका चयन हो जाएगा।

याचिका पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब करते हुए नियुक्तियों को याचिका के निर्णय के अधीन रखा है।

होर्मुज़ को लेकर अमेरिका व ईरान में फिर भड़का तनाव

अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हैगसेथ ने कहा सीज़फायर लागू है पर होर्मुज़ के लिए अलग से अभियान चल रहा है

वॉशिंगटन/तेहरान, 05 मई। पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर बढ़ता दिख रहा है, जहां ईरान और अमेरिका के बीच स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को लेकर स्थिति बेहद संवेदनशील बनी हुई है। हालात ऐसे हैं कि सीज़फायर की घोषणा के बावजूद दोनों पक्षों की सैन्य गतिविधियां जारी हैं।

- ईरान ने अमेरिका को और गंभीर स्थिति पैदा होने की चेतावनी दी।

अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने स्पष्ट किया है कि सीज़फायर अभी भी लागू है और इसे खत्म नहीं माना जा सकता। उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में जहाजों की सुरक्षा के लिए चलाया जा रहा अभियान अलग और सीमित प्रकृति का है। उन्होंने यह भी कहा कि यह ऑपरेशन केवल वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षा के लिए अस्थायी व्यवस्था है।

रक्षा मंत्री हेगसेथ ने पेंटागन ब्रीफिंग में कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों को निकालने का अमेरिकी प्रयास ऑपरेशन एपिक फ्यूरी से अलग है। उन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट फ्रीडम रक्षात्मक प्रकृति का अभियान है। इसका दायरा सीमित है और यह अस्थायी अवधि के लिए है। इस अभियान का एकमात्र मिशन ईरानी आक्रामकता से निर्दोष वाणिज्यिक जहाजों की रक्षा करना है।

रक्षा मंत्री ने बताया कि दो अमेरिकी वाणिज्यिक जहाज जलडमरूमध्य से सफलतापूर्वक गुजर चुके हैं। इसके अतिरिक्त, छह अन्य जहाजों ने ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी का उल्लंघन करने का प्रयास किया था। इन सभी जहाजों को वापस भेज दिया गया।

ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को लेकर संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है और स्थिति आगे और गंभीर हो सकती है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने कड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाया गया तो ईरान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।

कतर के आसमान से अमेरिकी विमान केसी-135 लापता

यह विमान मिडिल ईस्ट में चल रहे सैन्य अभियानों में सहायता दे रहा था

वॉशिंगटन, 05 मई। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका की वायुसेना का एक केसी-135 स्ट्रैटोटैंकर विमान अचानक लापता हो गया है। यह विमान कतर के ऊपर उड़ान भर रहा था, तभी अचानक यह रडार स्क्रीन से गायब हो गया। इस घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों में चिंता बढ़ गई है।

- विमान ने उड़ान भरते समय इमरजैंसी कोड भेजा था, उसके बाद वह रडार से गायब हो गया।

फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइटरडार 24 के अनुसार, इस विमान ने उड़ान के दौरान 7700 इमरजेंसी कोड भेजा था। यह कोड किसी गंभीर तकनीकी खराबी या आपात स्थिति का संकेत होता है। इसके कुछ समय बाद विमान का संपर्क पूरी तरह टूट गया और वह रडार से गायब हो गया।

रिपोर्ट के मुताबिक, यह केसी-135 विमान संयुक्त अरब अमीरात के अल धफरा एयर बेस पर तैनात था तथा मिडिल ईस्ट में चल रहे सैन्य अभियानों में सहायता कर रहा था। ट्रैकिंग डेटा में देखा गया कि विमान पहले कुछ समय तक हवा में चक्कर लगाता रहा और फिर नीचे उतरने की कोशिश करने लगा, लेकिन इसके बाद उसका संपर्क टूट गया।

अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि विमान के साथ क्या हुआ। न तो किसी हादसे की पुष्टि हुई है और न ही किसी हमले की आधिकारिक जानकारी सामने आई है। जांच एजेंसियां इस पूरे मामले की जानकारी जुटाने में लगी हुई हैं। यह पहली बार नहीं है, जब केसी-135 विमान को लेकर ऐसी स्थिति सामने आई हो। इससे पहले मार्च महीने में भी ईरान युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना का एक केसी-135 विमान लापता हो गया था।

जहाँ एसआईआर में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

एनडीटीवी द्वारा किए गए एक विश्लेषण में दिखाया गया कि इनमें से अधिकांश सीटें भाजपा के पक्ष में गईं। पार्टी ने इन 147 सीटों में से 95 सीटें जीतीं, जबकि तृणमूल ने लगभग आधी, यानी 51 सीटें जीतीं। कांग्रेस ने केवल एक सीट पर जीत दर्ज की।

कुल 67 सीटों पर 15,000 से 25,000 नाम काटे गए थे, वहां भाजपा फिर विजेता बनी। इनमें भाजपा ने 47 सीटें जीतीं, तृणमूल ने 19 सीटें और कांग्रेस ने एक सीट जीती।

62 सीटों में, जहां 5,000 से 15,000 के बीच नाम हटाए गए थे, में भाजपा ने 50 सीटें जीतीं और बाकी तृणमूल ने हासिल कीं। उन सभी 13 सीटों पर, जहां 5,000 से कम वोटर्स के नाम कटे, भाजपा ने जीत दर्ज की।

निर्णय प्रक्रिया के दौरान, "बहिष्कृत करने योग्य" मामलों की संख्या सबसे ज्यादा मुर्शिदाबाद जिले से थी। यहां 4.55 लाख से अधिक नाम हटाए गए, उसके बाद नॉर्थ 24 परगना (3,25,666) और मालदा (2,39,375) का स्थान है। मुर्शिदाबाद में, तृणमूल ने 2021 में 22 में से 20 सीटें जीती थीं; इस बार केवल नौ सीटों पर जीत मिली, जिससे अल्पसंख्यक वोटों में विभाजन और भाजपा के पक्ष में हिंदू वोटों का समेकन दिखा। नॉर्थ 24 परगना में भी यही प्रवृत्ति रही। इस जिले की 33 सीटों में से तृणमूल ने 2021 में 28 सीटें जीती थीं, जो इस बार केवल आठ रह गईं। मालदा की 12 सीटों में पार्टी का हिस्सा 2021 में आठ से घटकर इस बार छह सीटों तक रह गया। बाकी सभी सीटें भाजपा ने जीतीं।

कौन होगा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इस पद के लिए आदर्श उम्मीदवार बन सकती हैं। पॉल 2019 से 2024 तक लोकसभा सांसद रह चुकी हैं। पार्टी पदाधिकारियों का कहना है कि समिक भट्टाचार्य को इसलिए भी उपयुक्त माना जा सकता है, क्योंकि उनके नेतृत्व में पार्टी ने बंगाल के विधानसभा चुनाव में पहली बार जीत हासिल की। भट्टाचार्य वर्तमान में राज्यसभा सदस्य हैं।

ट्रंप ने मोदी को बधाई दी

वॉशिंगटन, 05 मई। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की ऐतिहासिक जीत के बाद देश ही नहीं, बल्कि दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इसी क्रम में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐतिहासिक और निर्णायक चुनावी जीत की बधाई दी है।

- विधानसभा चुनावों में मिली जीत को एतिहासिक जनादेश बताया ट्रंप ने।

इस ऐतिहासिक जीत और ट्रंप की बधाई को भारत की बढ़ती वैश्विक साख से भी जोड़कर देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भारत-अमेरिका संबंधों को और मजबूती मिलेगी और वैश्विक राजनीति में भारत की भूमिका और प्रभावशाली होगी।

'सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 की जाएगी'

नई दिल्ली, 05 मई। केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस संबंध में सरकार संसद में विधेयक लाएगी। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश समेत 34 न्यायाधीश हैं। इसे बढ़ाकर कुल 38 किया जाएगा।

- प्र.मंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में इस संबंध में संशोधन विधेयक पेश करने को मंजूरी दी गई।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को संसद में सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 को पेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

सरकार का कहना है कि न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि से सर्वोच्च न्यायालय अधिक कुशलता और प्रभावी ढंग से कार्य कर सकेगा और त्वरित न्याय सुनिश्चित कर सकेगा।

7 मई को सम्राट चौधरी मंत्रिमण्डल का विस्तार होगा

पटना, 05 मई। बिहार की राजनीति में इन दिनों हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। इस बहुप्रतीक्षित विस्तार को लेकर आधिकारिक घोषणा भी कर दी गई है।

- पटना के एतिहासिक गांधी मैदान में होगा शपथ ग्रहण समारोह

बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष संजय सरावगी ने मंगलवार को जानकारी दी कि 7 मई को मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा, जिसमें कई बड़े राष्ट्रीय नेता शामिल होंगे।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के मुताबिक, समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उपस्थिति तय मानी जा रही है। इसके अलावा, गृह मंत्री अमित शाह, केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, केन्द्रीय मंत्री चिराग पासवान, केन्द्रीय मंत्री जितन राम मांझी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार समेत, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के कई दिग्गज नेताओं के शामिल होने की संभावना है।

सूत्रों के अनुसार, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के शीर्ष नेतृत्व द्वारा नए मंत्रियों के नाम लगभग तय कर लिए गए हैं। शपथ ग्रहण को लेकर गांधी मैदान में तैयारियां जोरों पर हैं। वहां एक भव्य मंच का निर्माण किया जा रहा है, साथ ही विशिष्ट अतिथियों, जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों के लिए बैठने की व्यापक व्यवस्था की जा रही है।

प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था, यातायात नियंत्रण और भीड़ प्रबंधन को लेकर विस्तृत योजना बनाई जा रही है, ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके।

उल्लेखनीय है कि 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दो उपमुख्यमंत्रियों के साथ शपथ ली थी।

'मैं इस्तीफा नहीं ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

टीएमसी सुप्रीमो ने दावा किया कि उनकी पार्टी ने वास्तव में जनमत नहीं खोया, तथा आरोप लगाया कि लगभग 100 सीटों को "जबरन छीना गया।" उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त पर चुनाव में "खलनायक" की भूमिका निभाने का आरोप लगाया और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए तथा मतदान के बाद असामान्य रूप से उच्च बैटरी स्तर को लेकर चिंता जताई।

उन्होंने कहा, "सीईसी इस चुनाव में जनता के लोकतांत्रिक अधिकार लूटने वाले विलेन बन गए, और ईवीएम मशीन को लूटने के लिए। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मतदान के बाद ईवीएम मशीन 80 से 95 प्रतिशत चार्ज कैसे रह सकती है? यह कैसे संभव है?"

ममता ने आरोप लगाया कि चुनाव भारत के चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी के समन्वित प्रयासों से प्रभावित हुए, और दावा किया कि शीर्ष नेतृत्व, जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हैं, ने सीधा हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा, "भाजपा ने सीधे चुनाव आयोग के साथ मिलकर खेल खेला। आप इसे "बैटिंग" कह सकते हैं। हम पूरी मशीनरी के खिलाफ लड़े, जिसमें प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी शामिल थे, मैंने अपने जीवन में ऐसा चुनाव कभी नहीं देखा।" ममता ने चुनाव को गंदा, नीच और शरारती प्रक्रिया कहा।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मतदान से पहले के दिनों में उनके पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी और छापेमारी की गई। ममता के अनुसार, प्रशासनिक फेरबदल, जिसमें आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की नियुक्ति और स्थानांतरण शामिल थे, परिणाम को प्रभावित करने के लिए किए गए। "चुनाव से दो दिन पहले उन्होंने हमारे लोगों को अंधाधुंध गिरफ्तार करना शुरू किया, उन्होंने हर जगह छापेमारी शुरू कर दी।"

बनर्जी ने "चुनाव के बाद की हिंसा से प्रभावित" क्षेत्रों का दौरा करने और वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए 10 सदस्यीय तथ्य-जाँच समिति गठित करने की घोषणा की।

उन्होंने 2021 में पोस्ट-पोल हिंसा के आरोपों को आधारहीन बताया।

बनर्जी ने कहा कि विपक्षी इंडिया ब्लॉक के कई नेताओं ने चुनाव परिणाम के बाद उनके साथ एकजुटता व्यक्त की। उन्होंने कहा, "इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने मुझे एकजुटता दिखाने के लिए कॉल किये। सोनिया जी और राहुल गांधी ने मुझसे बात की।"

बनर्जी ने कहा कि अब वे राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी गठबंधन को मजबूत करने पर ध्यान देंगी।

ज्ञातव्य है कि भाजपा ने 294-सदस्यीय विधानसभा में निर्णायक बहुमत हासिल किया और 207 सीटें जीतकर टीएमसी के 15 साल के शासन का अंत किया।

टीएमसी नेता ने मतदाता सूची को लेकर भी चिंता जताई तथा कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान लगभग 90 लाख नाम हटा दिए गए। उन्होंने कहा कि अदालत के हस्तक्षेप के बाद 32 लाख नाम बहाल किए गए, लेकिन विसंगतियां बनी रहीं और कथित तौर पर अतिरिक्त नाम पारदर्शिता के बिना जोड़ दिए गए।

2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की निर्णायक जीत हुई, जो राज्य में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव दर्शाती है और टीएमसी के लंबे समय से चले आ रहे शासन का अंत करती है।

गत लोकसभा में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मददगार रहा। भाजपा के स्टार प्रचारक और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा द्वारा जोरहाट में आयोजित मेगा रैलियों और यात्राओं का जनता ने स्वागत किया।

युवाओं का एक हिस्सा, जो गौरव गोगोई का समर्थन करने वाला माना गया था, मतदान के दौरान क्षेत्र में अनुपस्थित था, जिससे उनके वोट शेयर पर असर पड़ा।

एक खामोश लेकिन महत्वपूर्ण कारक असम के केन्द्रीय विदेश राज्य मंत्री और राज्यसभा सांसद पबित्रा मार्गेरिटा का जोरहाट को अपना "बेस" बना लेना भी रहा।

भाजपा के पबित्रा मार्गेरिटा, जो गौरव गोगोई की तरह 'अहोम' समुदाय से हैं, ने जोरहाट में लगातार जमीनी संपर्क के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी सहज उपलब्धता और लगातार जन संपर्क ने मतदाताओं की धारणा भाजपा के पक्ष में बनाने में मदद की।

गोस्वामी, जो गौरव गोगोई की तुलना में काफी छोटे कद के नेता हैं, ने मुद्दा आधारित और प्रभावी चुनाव अभियान चलाया, जिसमें आक्रामक भाषणों से बचा गया। राष्ट्रीय स्तर पर गौरव की ताकत को स्वीकार करते हुए और खुद को प्रतिबद्ध स्थानीय नेता के रूप में प्रस्तुत करते हुए, उन्होंने मतदाताओं के दिल को छू लिया।

जोरहाट का परिणाम यह दिखाता है कि चुनावी राजनीति में जमीनी संपर्क, स्थानीय विश्वसनीयता और नैरेटिव नियंत्रण कितने ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। कांग्रेस और विशेष रूप से गौरव गोगोई के लिए यह परिणाम असम में अपनी रणनीति की पुनः समीक्षा करने और आत्म-विश्लेषण करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है।

'तमिलनाडु ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

थे। उन्होंने यह भी कहा कि अगर राहुल गांधी विजय के साथ चुनाव लड़ते, तो वे 180-190 सीटें जीत सकते थे।

चोडणकर ने कहा, "स्थानीय नेता, जमीनी स्तर के नेता सुझाव दे रहे थे कि अगर राहुल गांधी, जिनकी तमिलनाडु में व्यापक स्वीकृति है, विजय के साथ अभियान में शामिल होते, तो इसका बड़ा प्रभाव पड़ता और हम तमिलनाडु के चुनावों में धूम मचा सकते थे और लगभग 180-190 सीटें जीत सकते थे।"

लंदन से न्यूयॉर्क तथा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

भारत में लंबी यात्रा का समापन है।"

दूसरे प्रमुख ब्रिटिश अखबार, द गार्जियन ने भी बंगाल के परिणामों पर ध्यान केन्द्रित किया और कहा कि इस राज्य, जो विपक्ष का एक दुर्लभ गढ़ रहा है, को देश भर में भाजपा की सत्ता को मजबूत करने में बेजोड़ कहा जा सकता है।

"नरेन्द्र मोदीज़ बीजेपी विन्स इलैक्शन इन वैस्ट बैंगॉल फॉर द फर्स्ट टाइम" शीर्षक वाले लेख में कहा गया कि बंगाल विधानसभा चुनाव के परिणाम "भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेंगे और पहले से कमजोर विपक्ष को एक और हतोत्साहित करने वाला एक और झटका लगेगा।"

अमेरिका में, न्यूयॉर्क टाइम्स ने "मोदीज़ हिंदू नैशनलिस्ट्स कॉन्कर अ बैस्टियन ऑफ इण्डियाज़ ऑपोजिशन" शीर्षक वाली रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल में भाजपा के प्रदर्शन को 'ऐतिहासिक' बताया।

इसमें कहा गया कि पीएम मोदी की भाजपा ने "दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को फिर से बनाने के अपने दशकों पुराने अभियान में सोमवार को नई उपलब्धि हासिल की, और देश के सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों में से एक में विधानसभा चुनाव जीता, जहां वह पहले कभी शासन के करीब भी नहीं पहुँची थी।"

रिपोर्ट में तमिलनाडु में विजय की अप्रत्याशित जीत पर भी चर्चा की गई। रिपोर्ट में कहा गया, "दिन के सबसे बड़े आश्चर्यों में से एक तमिलनाडु में था, जहां एक राजनीतिक नौसिखिया अभिनेता जोसेफ विजय चंद्रशेखर की पार्टी ने राज्य की स्थापित पार्टियों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया।

वॉशिंगटन पोस्ट ने अपने कवरेज में कहा कि पश्चिम बंगाल में चुनावी परिणाम पीएम मोदी की "छवि को बढ़ावा देंगे और उनके तीसरे कार्यकाल के मध्य में उनकी स्थिति को मजबूत करेंगे। लेख में कहा गया, "2024 के राष्ट्रीय चुनाव ने उनकी सत्ताधारी पार्टी को सरकार बनाने के लिए क्षेत्रीय सहयोगियों पर निर्भर होना पड़ा। लेख में कहा गया, "उम्मीद है कि वे 2029 में रिकॉर्ड चौथी बार चुनाव लड़ेंगे।

रिपोर्ट में केरल पर भी ध्यान केन्द्रित किया गया, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस-नेतृत्व वाली विपक्षी पार्टी ने सत्तारूढ़ वामपंथी सरकार को परास्त किया, और अपने अंतिम गढ़ों में से एक पर वामपंथी शासन का अंत किया।

पाकिस्तान में, द डॉन अखबार ने चुनावों पर एएफपी की रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें कहा गया कि पीएम मोदी की "राष्ट्रवादी पार्टी" ने "विपक्ष के गढ़ पश्चिम बंगाल राज्य में महत्वपूर्ण चुनावों में जीत हासिल की, जो लंबे समय से उसके प्रतिद्वंद्वी के नियंत्रण में था।"

रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इन परिणामों के बाद पीएम मोदी "2029 में आम चुनाव से पहले अधिक बेरोजगारी दर और एक लंबित ट्रेड डील सहित कई आर्थिक और विदेश नीति चुनौतियों से जूझते हुए मजबूत स्थिति में होंगे।"

बांग्लादेश के ढाका ट्रिब्यून ने भी वही एएफपी रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें एक और बड़े चुनावी झटके का उल्लेख किया गया, जिसमें दक्षिणी राज्य तमिलनाडु के वरिष्ठ राजनेता एम.के. स्टालिन अपनी सीट एक अनजाने प्रतिद्वंद्वी को हार गए।

रिपोर्ट में कहा गया कि स्टालिन की सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कज़गम (डी.एम.के.) पार्टी पीछे छूट गई और अभिनेता-राजनेता सी. जोसेफ विजय की नई पार्टी को पहला स्थान मिला।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2009/28296 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600